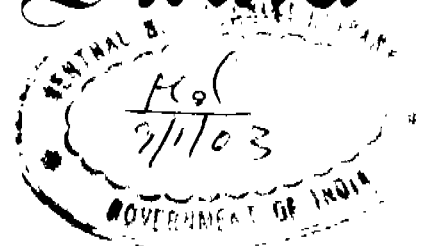




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 198]
No. 198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2002/आश्विन 5, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2002/ASVINA 5, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2002

सं. टीएएमपी/8/2002-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की भाग 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कॉपर ऐनोड की घाट शुल्क दर निर्धारित करने संबंधी तृतीकोरिन पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/8/2002-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश

(सितंबर, 2002 के 20वें दिन पारित)

यह मामला कॉपर ऐनोड की घाटशुल्क दर निर्धारित करने के संबंध में तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. टीपीटी ने वर्तमान समय में सान्द्रित कॉपर पर लागू घाटशुल्क दर के आधार पर कॉपर ऐनोड के लिए 55/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। टीपीटी ने प्रशुल्कों में सामान्य संशोधन के अपने प्रस्ताव में, वर्तमान प्रशुल्कों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, सान्द्रित कॉपर की प्रस्तावित घाटशुल्क दर के अनुसार कॉपर ऐनोड के लिए 61/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर का प्रस्ताव किया गया है।

2.1. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :-

- (i). वर्ष 1998 में पहली बार इस पत्तन से कॉपर ऐनोड भेजा गया था। चूंकि उस समय इस कार्गो की दर मौजूद नहीं थी, इसलिए उक्त कार्गो को अनुसूची 'ख' के अधीन बक बल्क कार्गो पर लागू 'सामान्य आधुनिकीकरण' के रूप में वर्गीकृत कर 0.3% यथामूल्य की दर से घाटशुल्क वसूल किया गया था।

- (ii). यथामूल्य दर लागू करके लगभग 230/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर परिकलित की गई है। यह दर (टन आधार पर वसूल की जाने वाली) किसी अन्य कार्गो की दरों के मान की अनुसूची 'क' में उपलब्ध घाटशुल्क दरों की तुलना में बहुत अधिक है।
- (iii). मै. स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) ने पत्तन से अनुरोध किया है कि कॉपर ऐनोड की दरों के मान की अनुसूची 'क' के अधीन बल्क कार्गो पर लागू 'अन्यथा अविनिर्दिष्ट मर्दे' के रूप में वर्गीकृत करके इसके लिए 42/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित की जाए।
- (iv). सान्द्रित कॉपर कच्चा माल है, इसका वर्तमान घाटशुल्क दर 55/- रुपये प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है। इस तथ्य के आलोक में कि तैयार उत्पाद की घाटशुल्क दर कच्चे माल की घाटशुल्क दर से कम नहीं हो सकती, पत्तन ने कॉपर ऐनोड के लिए सान्द्रित कॉपर पर यथा लागू 55/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।
- (v). टीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा इस शर्त पर 55/- रुपये प्रति मी.ट. की प्रस्तावित घाटशुल्क दर प्रयोगात्मक आधार पर अनुमोदित की गई थी कि प्रस्तावित नौभरण के लिए (जिस की, 2001 के प्रथम सप्ताह के दौरान मै0 स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज़ द्वारा प्रहस्तित किए जाने की संभावना थी, परंतु यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख तक प्रहस्तित नहीं किया गया) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा घाटशुल्क दर निर्धारित करने से उत्पन्न अंतर राशि का, यदि कोई हो, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के अन्दर पोतवणिक द्वारा भुगतान किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

2.2. टीपीटी के न्यासी बोर्ड ने दिनांक 3 नवंबर, 2001 के संकल्प संख्या 91 द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया था।

3. तत्पश्चात्, टीपीटी ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2002 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से 3 नवंबर, 2001 से पूर्व प्रभाव से कॉपर ऐनोड की घाटशुल्क दर निर्धारित करने के लिए अनुमोदन देने की मांग की गई थी।

4. विचार-विमर्श की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में, टीपीटी का प्रस्ताव विभिन्न संबद्ध संस्थाओं/ पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। उनसे प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है :-

तृतीकोरिन चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (टीसीसीआई)

परिपक्व कच्चे माल के रूप में आयात किया जाता है और यदि कच्चे माल को अधिक शोधन के किसी तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है तो इस पर घाटशुल्क प्रभार अत्यधिक से कम वसूल किए जाने चाहिए। यह कहकर यहाँ उल्टा तर्क दिया गया है कि जिस दर पर आयात किया गया है, दरें उससे कम नहीं हो सकती।

मै0 स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज़ (एसआईएल) .

- (i). वर्तमान में सिलवासा में अपने निजी संयंत्र तक कॉपर ऐनोड का परिवहन करने के लिए 1350/- रुपये प्रति मी.ट. का सड़क मार्ग किराये का (द्वार से द्वार) भुगतान किया जा रहा है और मार्गस्थ समय केवल 5 दिन है।
- (ii). पत्तन यथामूल्य घाटशुल्क दर वसूल कर रहा था, जोकि वर्ष 1998 में टीपीटी से प्रेषित कॉपर ऐनोड के प्रथम पार्सल पर 230/- रुपये प्रति मी.ट. परिकलित किया गया था। वसूल की गई घाटशुल्क दर अधिक थी और इसलिए इसके पश्चात् समुद्र द्वारा कुछ भी प्रेषित नहीं किया गया था। यह अब समुद्र मार्ग से कॉपर ऐनोड के परिवहन की संभावना का पता लगा रहा है, बशर्त घाटशुल्क प्रभार न्यूनतम हों।
- (iii). अन्य महापत्तनों में लौह और अलौह धातुओं के लिए घाटशुल्क प्रभार समान है। लौह और इस्पात की घाटशुल्क दर 35/- रुपये प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है। चूंकि, अलौह धातु के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है इसलिए कॉपर ऐनोड से भी अलौहयुक्त धातु होने के कारण 35/- रुपये प्रति मी.ट. की यही दर

वसूल की जाए। इससे कार्गो की आयाजाही को बढ़वा मिलेगा और पत्तन को अतिरिक्त कारोबार और राजस्व मिलेगा।

- (iv). चूंकि, वर्तमान दरों के मान में अलौह धातु के लिए कोई घाटशुल्क दर निर्धारित नहीं है, इसलिए इसने पत्तन से कॉपर ऐनोड के लिए 'अन्यथा अविनिर्दिष्ट वस्तुओं' के यथा लागू 42/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित करने का अनुरोध भी किया था।
- (v). घाटशुल्क दर वसूल करने के प्रयोजन से 'अयस्कों और खनिजों' के अधीन सान्द्रित कॉपर को वर्गीकृत करने के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, कॉपर ऐनोड के लिए इसके कच्चे माल सान्द्रित कॉपर की घाटशुल्क दर पर, जोकि इस समय 55/- रुपये प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है, विचार नहीं किया जा सकता।
- (vi). पत्तन को जनवरी, 2002 के दौरान प्रेषित किए गए 1000 मी.ट. के परीक्षण नौभरण के लिए 55/- रुपये प्रति मी.ट. की दर से वसूल किए गए घाटशुल्क की अंतर राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए।

इंडियन चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईसीसीआई)

इसने 'कॉपर ऐनोड' के लिए 55/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क निर्धारित करने के टीपीटी के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एआईसीसीआई)

- (i). लौह और अलौह दोनों धातुओं के घाटशुल्क प्रभार समान हैं और, इसलिए, कॉपर ऐनोड के लिए भी लौह और इस्पात की एकसमान दर 35/- रुपये प्रति मी.ट. पर विचार किया जा सकता है।
- (ii). कॉपर ऐनोड एक अलौह धातु है। चूंकि, दरों के मान में अलौह धातु के लिए घाटशुल्क दर निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कॉपर ऐनोड को 'अन्यथा अविनिर्दिष्ट वस्तुओं' के रूप में वर्गीकृत किया जाए, जिसके लिए 42/- रुपये प्रति मी.ट. प्रशुल्क निर्धारित किया गया है।
- (iii). सान्द्रित कॉपर का घाटशुल्क, कॉपर ऐनोड का घाटशुल्क निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि सान्द्रित कॉपर का वर्गीकरण विवादित है। इस संबंध में अभ्यावेदन महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के विचाराधीन है।
- (iv). टीपीटी के माध्यम से कॉपर ऐनोड का तटीय परिवहन केवल तभी वास्तविकता बन जाएगा जब यदि लागत कम होगी।
- (v). कॉपर ऐनोड का घाटशुल्क प्रभार 35/- रुपये प्रति मी.ट. निर्धारित करने का मै. एसआईएल का अनुरोध औचित्यपूर्ण है। यह श्रेणी वर्गीकरण की पात्रता को पूरा करता है और, इसलिए, स्वीकार किया जाए।

फ्रेडरेशन ऑफ़ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़ (एफआईएमआई)

इसके सदस्यों ने टीपीटी के प्रस्ताव पर कोई टिप्पणियाँ नहीं दी हैं।

5.1. विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियाँ टीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजी गई थीं।

5.2. टीपीटी ने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :-

- (i). ये दरें प्रदान की गई सेवा प्रदान करने की लागत पर और व्यापार क्या वहन कर सकता है, इस सिद्धांत पर आधारित हैं। यह दावा उचित नहीं है कि कम की गई घाटशुल्क दर स्वतंत्र पत्तन के लिए आदर्श प्रस्ताव होगा।
- (ii). आयात शुल्क और शुल्क वापसी मुद्दे सरकार की नज़र में हैं। पत्तन के घाटशुल्क भार किसी भी प्रकार से इससे संबंधित नहीं हैं।

- (iii). यह तथ्य इसके मामले में उचित नहीं है कि अन्य पत्तनों में लौह और अलौह धातुओं की घाटशुल्क दरें एकसमान हैं, क्योंकि विभिन्न महापत्तनों में सेवा प्रदान करने की लागत, संरचना और कार्गो की मात्रा भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए, लौह और इस्पात की घाटशुल्क दरों की तुलना कॉपर ऐनोड के साथ करना स्वीकार्य नहीं है।
- (iv). सान्द्रित कॉपर की घाटशुल्क दर 55/- रुपये प्रति मी.ट. निर्धारित करने का प्रस्ताव वर्ष 1997 में थोड़ा पत्तन न्यास में प्रचलित दर पर आधारित था। इसलिए, यह दावा कि उक्त दर स्वीकार्य नहीं है किसी भी प्रकार से विचार योग्य नहीं है।
- (v). कॉपर ऐनोड को बल्क कार्गो मानकर उसकी घाटशुल्क दर को 230/- रुपये प्रति मी.ट. (0.3% यथामूल्य पर आधारित) से कम कर 55/- रुपये प्रति मी.ट. करने का प्रस्ताव पत्तन द्वारा तटीय व्यापार में सुधार की इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है। और अधिक कमी करने का अनुरोध अनुचित है क्योंकि इससे लागतों की वसूली से होने वाली पत्तन की प्राप्तियों में कमी आएगी।
- (vi). पत्तन द्वारा वसूल किए गए अधिक प्रभारों को वापस करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 और 49 के उपबंधों के संबंध में दिए गए निर्णय का पालन किया जाए। यह इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर किया जाए।

इस मामले की संयुक्त सुनवाई 6 जून, 2002 को टीपीटी में आयोजित की गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए थे :-

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

- (i). कॉपर ऐनोड के लिए पहले 0.3% यथा मूल्य की दर से वसूली की जा रही थी। यह 230/- रुपये प्रति मी.ट. परिकलित किया गया था, जिसे अधिक समझा गया था। इसे 55/- रुपये प्रति मी.ट. करने का प्रस्ताव किया गया, ताकि स्टैलाइट इंडस्ट्रीज (तूतीकोरिन) इसे सड़क मार्ग के स्थान पर तटीय जलयानों द्वारा सिलवासा भेज सके।
- (ii). हम मात्रा छूट के बारे में चर्चा करेंगे। अगले सामान्य संशोधन के लिए कुछ निर्धारित किया जा सकता है।

मै. स्टैलाइट इंडस्ट्रीज (एसआईएस)

- (i). 55/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क अब आकर्षक नहीं रह गया है। हमें यह कार्य सड़क परिवहन से जारी रखना पड़ेगा। परंतु, टीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर यह हमारे लिए किसी स्तर तक युक्तिसंगत हो जाएगा।
- (ii). हम लोहद्रावक (स्मेल्टर) संयंत्र के लिए अपनी विस्तार योजनाओं के संदर्भ में टीपीटी के साथ मात्रा बढ़ाने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मात्रा छूट की कुछ व्यवस्था की जा सकती है।
- (iii). आज भी हम मात्रा छूट के इच्छुक हैं। यह हमारे अभ्यावेदन में है। अगले संशोधन तक प्रतीक्षा क्यों की जाए?

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i). टीपीटी की घाटशुल्क अनुसूची में कॉपर ऐनोड के लिए विशेष प्रविष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में, इस वस्तु के घाटशुल्क का भुगतान घाटशुल्क अनुसूची के अवशिष्ट उपबंध के अधीन किया जा रहा है। चूंकि, इस अवशिष्ट मद की यथामूल्य घाटशुल्क दर बहुत अधिक है, इसलिए टीपीटी ने कॉपर ऐनोड के लिए निश्चित प्रति टन घाटशुल्क दर का प्रस्ताव किया है।
- (ii). टीपीटी के प्रस्ताव में स्पष्ट की गई पृष्ठभूमि से पता चलता है कि एसआईएस बल्क वस्तुओं की दरों के मान में उपलब्ध अवशिष्ट दर में विस्तार कर कॉपर ऐनोड के लिए 42/- रुपये प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित करने का अनुरोध करता रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि कॉपर ऐनोड को बल्क वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। इस शंका के बावजूद, ऐसी स्थिति में घाटशुल्क अनुसूची की

अवशिष्ट प्रविष्टि को अपनाता उचित प्रतीत नहीं होता जब इस वस्तु की विशेष प्रविष्टि लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित हो।

- (iii). एसआईएल ने घाटशुल्क प्रसार वसूल करने के प्रयोजन से लौह और अलौह वस्तुओं को समान मानने की कुछ अन्य पत्तन न्यासों में प्रचलित पद्धति का उल्लेख किया है। अधिकारिक रूप से यह कहीं नहीं दर्शाया है कि इस पद्धति के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अधिकारिक निर्णय लिया गया है। अन्य पत्तनों में ऐसा होना संयोग मात्र है। इसके अलावा, इससे पहले कई अवसरों पर यह प्राधिकरण कह चुका है कि प्रशुल्क निर्धारण की मानक संकल्पनाएँ, सिद्धांत और दृष्टिकोण महापत्तनों पर एकसमान हो सकते हैं (और होने चाहिए); और किसी वर्ग विशेष की दरें, एकसमान होना आवश्यक नहीं है (नहीं हो सकती)। ऐसी स्थिति में, टीपीटी में घाटशुल्क दरें वसूल करने के लिए लौहयुक्त और अलौहयुक्त को समान धरातल पर रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।
- (iv). घाटशुल्क दर वसूल करने के प्रयोजन से सान्द्रित कॉपर के वर्गीकरण के बारे में एसआईएल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पृथक मामले के रूप में कार्यावाही की जा रही है। उस मामले में, उल्लिखित कारणों से, यह प्राधिकरण एसआईएल के अभ्यावेदन को खारिज करता है और कॉपर ऐनोड की वर्तमान घाटशुल्क दर को जारी रखने का आदेश देता है। परंतु, वर्ग विशेष के मामलों में निर्णय नहीं देने के बारे में सरकार से प्राप्त 'निर्देश' के कारण यह प्राधिकरण उस मामले पर अंतिम रूप से विचार नहीं कर सकता। इस स्थिति के बावजूद, सान्द्रित कॉपर की उपयुक्त मात्रा छूट योजना शुरू करने के लिए टीपीटी के प्रशुल्कों में सामान्य संशोधन संबंधी मामले में इसका पहले से प्रस्ताव किया जा चुका है। प्रस्तावित मात्रा छूट योजना के अधीन होने के बावजूद, प्रथम स्लैब के लिए घाटशुल्क दर पुरानी दर अर्थात् 55/- रूपए प्रति मी.ट. बनी रहेगी।
- (v). अपने प्रत्युत्तर में भी टीपीटी ने तर्क दिया है कि प्रस्तावित दर सेवा प्रदान करने की लागत पर आधारित है, इसलिए इसने प्रस्तावित दर को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई विस्तृत लागत प्रस्तुत नहीं की है। महापत्तनों की लेखांकन प्रणाली के मद्देनजर, हमें भी उस एक वस्तु के लागत व्योरे प्रस्तुत करने में कठिनाइयों हो रही हैं जो किसी खास मात्रा में प्रहस्तित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, इस प्राधिकरण को प्रस्ताव की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर अपना निर्णय देना होगा। टीपीटी का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता कि कच्चे माल (सान्द्रित कॉपर) से 55/- रूपए प्रति मी.ट. घाटशुल्क वसूल किया जाता है और तैयार उत्पाद की घाटशुल्क दर कच्चे माल की दर से कम नहीं हो सकती। इसके अलावा, प्रति टन घाटशुल्क दर लागू करना यथामूल्य के स्थान पर भार/मात्रा के आधार पर और मदों के लिए दरें रखने के इस प्राधिकरण के सुझाव के अनुसार है।
- (vi). रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों से पता चलता है कि टीपीटी में कॉपर ऐनोड का यातायात नगण्य है। जब मात्रा पर्याप्त हो जाएगी, तब इस वस्तु के लिए मात्रा छूट योजना शुरू करने के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।
- (vii). टीपीटी ने घाटशुल्क दर निर्धारण को 3 नवंबर, 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध इसलिए किया गया है क्योंकि यह वस्तु के वर्गीकरण को अवशिष्ट प्रविष्टि के अधीन बनाए रखने के बावजूद कॉपर ऐनोड को प्रस्तावित दरों पर प्रहस्तन करने की अनुमति पहले ही दे चुका है। टीपीटी द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाए जाने से वास्तव में पोटवणिक को लाभ हुआ है, क्योंकि यथामूल्य दर प्रस्तावित दर से कम से कम चार गुना अधिक होगी। इस स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण टीपीटी के प्रस्ताव को 3 नवंबर, 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करता है।

8. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण कॉपर ऐनोड की घाटशुल्क दर 55/- रूपए प्रति मी.ट. निर्धारित करने के टीपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है और तदनुसार 3 नवंबर, 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से टीपीटी की दरों के मान में संशोधन करता है।

एस सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2002

No. TAMP/8/2002-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38

of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Tuticorin Port Trust about fixation of wharfage rate for Copper Anode as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/8/2002-TPT

The Tuticorin Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 20th day of September 2002)

This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) about fixation of wharfage rate for Copper Anode.

1.2. The TPT has proposed to fix the wharfage rate for Copper Anode at Rs.55/- PMT based on the wharfage rate applicable at present for Copper Concentrate. In its proposal for a general revision of tariffs, the TPT has proposed a 10% increase in the existing tariffs. Accordingly, the wharfage rate for Copper Anode is proposed at Rs.61/- PMT in line with the wharfage rate proposed for Copper Concentrate.

2.1. The TPT has made the following main points in its proposal:

- (i). Copper Anode was shipped through this port for the first time in 1998. Since the rate for this cargo did not exist at that time, the wharfage was collected @ 0.3% advalorem, classifying the said cargo as 'Items not otherwise specified', applicable to break bulk cargo under schedule 'B'.
- (ii). The wharfage rate worked out to Rs.230/- PMT approximately by applying the advalorem rate. This appeared to be too high as compared to the wharfage rate available in schedule 'A' of the Scale of Rates for any other cargo (charged on tonnage basis).
- (iii). M/s. Sterlite Industries (India) Limited (SIL) have requested the port to fix the wharfage rate for Copper Anode at Rs.42/- PMT by classifying it as "Items not otherwise specified" applicable for bulk cargo under schedule 'A' of the Scale of Rates.
- (iv). The existing wharfage rate for Copper Concentrate, which is a raw material, is prescribed at Rs.55/- PMT. In the light of the fact that the wharfage rate for a finished product cannot be lower than that for a raw material, the Port has proposed to fix the wharfage rate for Copper Anode at Rs.55/- PMT as applicable to Copper Concentrate.
- (v). The proposed wharfage rate of Rs.55/- PMT was approved by the Board of Trustees of the TPT on an experimental basis subject to approval of the TAMP for the proposed shipment (expected to be handled by M/s. Sterlite Industries during the first week of November 2001; but, not handled till the date of submission of this proposal). The differential amount, if any, arising due to fixation of wharfage rate by the TAMP was proposed to be paid by the shipper within 15 days from the date of notification of the Order by the TAMP in the Gazette of India.

2.2. This proposal was approved by the Board of Trustees of the TPT vide Resolution number 91 dated 3 November 2001.

3. Subsequently, the TPT vide its letter dated 13 February 2002 has sought approval of this Authority for fixation of the wharfage rate for Copper Anode with retrospective effect from 3 November 2001.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of the TPT was circulated to various concerned bodies/representative bodies of port users for their comments. The comments received from them are summarised below:

Tuticorin Chamber of Commerce and Industry (TCCI)

The copper ore is imported as a raw material; and, if a raw material is converted into any finished product of greater refinement it has to be levied wharfage charges less than the Ore. The logic is inverted here to state that the rates cannot be less than what is imported.

Sterlite Industries (India) Limited (SIL)

- (i). At the present, road freight of Rs.1350/- PMT (for door to door) is being paid for transporting Copper Anode to its own plant at Silvassa; and, the transit time is merely 5 days.
- (ii). The port had levied an advalorem wharfage rate which worked out to Rs.230/- PMT on the first parcel of Copper Anode dispatched through the TPT in the year 1998. The wharfage rate levied was high; and, hence nothing was dispatched by sea thereafter. It is now exploring to transport Copper Anode by the sea route provided the wharfage charges are minimum.
- (iii). The wharfage charge is the same for ferrous and non-ferrous metals in the other major ports. The wharfage rate for Iron and Steel is prescribed as Rs.35/- PMT. Since no rate is specified for non-ferrous metal, Copper Anode may also be charged the same rate of Rs.35/- PMT, it being a non-ferrous metal. This will encourage movement of the cargo and bring in additional business and revenue to the port.
- (iv). Since the existing Scale of Rates does not prescribe any wharfage rate for non-ferrous metal, it had also requested the port to fix the wharfage rate for Copper Anode at Rs.42/- PMT as applicable to "Goods otherwise not specified".
- (v). A representation has been submitted to the TAMP for classifying Copper Concentrate under 'Ores and Minerals' for the purpose of charging wharfage rate. The wharfage rate for its raw material Copper Concentrate which is presently prescribed at Rs.55/- PMT shall, therefore, not be considered for Copper Anode.
- (vi). The Port may be directed to refund the differential wharfage collected @ Rs. 55/- PMT for the trial shipment of 1000 MT dispatched during January 2002.

Indian Chamber of Commerce and Industry (ICCI)

It endorses the proposal of the TPT to fix wharfage for 'Copper Anode' at Rs.55/- PMT.

All India Chamber of Commerce and Industry (AICCI)

- (i). The wharfage charge for both ferrous and non-ferrous materials are the same; and, hence, the same rate of Rs. 35 /- PMT for Iron and Steel may be considered for Copper Anode also.
- (ii). Copper Anode is a non-ferrous metal. Since the wharfage rate for non-ferrous is not prescribed in the SOR, Copper Anode may be classified as "Goods otherwise not specified" for which the tariff prescribed is Rs. 42 /- PMT.
- (iii). The wharfage for Copper Concentrate cannot be the basis for fixing wharfage for Copper Anode since the classification of Copper Concentrate is under dispute. The representation in this regard is under active consideration of the TAMP.
- (iv). Coastal transportation of Copper Anode through the TPT can be a reality only if the cost is economical.
- (v). The request of M/s. SIL to fix wharfage charge for Copper Anode at Rs.35/- PMT is justifiable. It meets the category classification; and, hence, may be conceded.

Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)

Its members have no comments to offer on the TPT proposal.

5.1. The comments received from the various port users were forwarded to the TPT as feed back information.

5.2. In response, the TPT has offered the following main points:

- (i). The rates are based on cost of rendering services and the principle of what the trade can bear. The contention that a reduced wharfage rate will be an ideal proposition for a free port is not relevant.
- (ii). The import duty and duty drawback are issues connected with policies of the Government. The Port's wharfage charges are not related to it at all.
- (iii). The fact that the wharfage rates for ferrous and non-ferrous metals in other ports are one and the same is not relevant in its case as the cost of rendering the service and the composition and volume of cargo are different amongst various major ports. The comparison of the wharfage rates of Iron and Steel with that of the Copper Anode is, therefore, not acceptable.
- (iv). The proposal for fixation of the wharfage rate for Copper Concentrate at Rs. 55/- PMT was based on the rate prevalent in the Chennai Port Trust in 1997. Hence, the contention that the above rate is not acceptable does not merit any consideration.
- (v). The proposal to reduce the wharfage rate of Copper Anode from Rs.230/- PMT (based on 0.3% advalorem) to Rs.55/- PMT by treating it as a bulk cargo reflects the desire of the port to improve the coastal trade. The request for a further reduction is not justified as the same will dilute the port's earnings to recover the costs.
- (vi). The decision of the Authority with respect of the provisions of Section 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 for refund of excess charges collected by the port will be complied with. This shall be done based on the rate approved by the Authority.

6. A joint hearing in this case was held on 6 June 2002 at the TPT. At the joint hearing, the following submissions were made:

Tuticorin Port Trust

- (i). Copper Anode was earlier charged @ 0.3% advalorem. This worked out to Rs. 230/- PMT which was considered high. This was proposed to be reduced to Rs. 55/-PMT so that it can go from Sterlite Industries (Tuticorin) to Silvassa by coastal vessels instead of by road.
- (ii). We will discuss about volume discount. May be something can be worked out for the next general revision.

M/s. Sterlite Industries Limited

- (i). Wharfage of Rs. 55/- PMT is not attractive now. We will continue with road transportation. But, accept the TPT proposal, it may become relevant to us at some stage.
- (ii). We can discuss with the TPT about increasing volume in the context of our expansion plans for the smelter plant. May be some volume discount arrangement can be worked out.
- (iii). Even today we are interested in volume discount. It is there in our representation. Why wait till the next revision?

7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The wharfage schedule of the TPT does not contain a specific entry for Copper Anode. In the event, this commodity has been subjected to payment of wharfage under the residuary provision in the wharfage schedule. Since the ad valorem wharfage rate for a residuary item is very high, the TPT has proposed a fixed per tonne wharfage rate for Copper Anode.

- (ii). The background explained in the proposal of the TPT shows that the SIL has been requesting for fixation of the wharfage rate at Rs.42 PMT for Copper Anode by extending the residuary rate available in the Scale of Rates for bulk commodities. It is not clear whether Copper Anode can be classified as a bulk commodity. Notwithstanding such doubt, it does not appear reasonable to go by a residual entry in the wharfage schedule when a specific entry for the commodity is proposed to be introduced.
- (iii). The SIL has quoted the practice obtaining at some other port trusts of giving the same treatment to ferrous and non-ferrous materials for the purpose of levying wharfage charges. There is nothing on record to show that such a practice flows from an authoritative decision of any competent authority. It may merely be a co-incidence at the other ports. Further, on several earlier occasions, this Authority has held that the norms, concepts, principles, and approach of tariff setting can (and, must) be uniform across the major ports; and, individual rates need not (and, cannot) be the same. That being so, treating ferrous and non-ferrous on the same footing for levying the wharfage rates at the TPT does not considered to be necessary.
- (iv). A representation filed by the SIL about classification of Copper Concentrate for the purpose of levying wharfage is being dealt with as a separate case. In that case, for stated reasons, this Authority could have rejected the representation of the SIL and ordered continuance of the existing wharfage rate for Copper Concentrate. But, because of a 'direction' from the Government about not adjudicating in individual cases, this Authority will not be able to finally consider that case. Notwithstanding this position, it has already been proposed, in the case relating to general revision of tariffs of the TPT, to introduce a suitable volume discount scheme for Copper Concentrate. Even under the proposed volume discount scheme, the wharfage rate for the first slab will continue to be the old rate i.e., Rs.55 PMT.
- (v). Even though, in its response, the TPT has argued that the proposed rate is based on cost of rendering services, it has not furnished any detailed costing to justify the proposed rate. Given the accounting system at the major ports, we also realise the difficulties in furnishing the cost details for one commodity which is not handled in any significant quantity. In this situation, this Authority may have to go by the reasonableness of the proposal and its own judgement. The argument of the TPT that the raw material (Copper Concentrate) is charged wharfage at Rs.55 PMT and the wharfage rate for a finished product cannot be lower than the rate for a raw material is found to be reasonable. Further, introduction of a per tonne rate of wharfage is in line with the suggestion of this Authority to have rates for more items based on weight/volume instead of being ad valorem.
- (vi). The facts available on record indicate that the traffic of Copper Anode at the TPT is negligible. When sufficient volume builds up, the issue of introducing a volume discount scheme for this commodity can be taken up for consideration.
- (vii). The TPT has requested for fixation of the wharfage rate with retrospective effect from 3 November 2001. This request has been made since it has already allowed Copper Anode handling at the proposed rates instead of continuing with the classification of the commodity under the residuary entry. This approach adopted by TPT has, in fact, benefited the shipper since the ad valorem rate would have been atleast four times higher than the proposed rate. In view of this position, this Authority is inclined to approve the proposal of the TPT with retrospective effect from 3 November 2001.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of the TPT for fixation of the wharfage rate for Copper Anode at Rs.55 PMT and amends the Scale of Rates of the TPT accordingly with retrospective effect from 3 November 2001.

S. SATHYAM, Chairman
[ADVT.III/IV/143/2002/Exty.]

